

निर्यात प्रोत्साहन मिशन: वैश्विक व्यापार में MSMEs के लिए एक एकीकृत मार्ग का निर्माण

UPSC प्रासंगिकता

- **GS 3:** भारतीय अर्थव्यवस्था – MSMEs, निर्यात नीति, सरकारी योजनाएं।
- **प्रारंभिक परीक्षा:** EPM की विशेषताएं, TRACE, LIFT, FLOW, ब्याज सहायता (Interest Subvention)।

चर्चा में क्यों?

- सरकार ने सात अतिरिक्त हस्तक्षेपों (interventions) को शुरू करके निर्यात प्रोत्साहन मिशन (EPM) का विस्तार किया है, जिससे इसके परिचालन घटकों की कुल संख्या दस हो गई है।
- नवंबर 2025 में ₹25,060 करोड़ के परिव्यय (FY 2025-26 से FY 2030-31) के साथ अनुमोदित यह मिशन, MSMEs, पहली बार निर्यात करने वालों और श्रम-गहन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ एक समन्वित और डिजिटल रूप से एकीकृत निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का प्रयास करता है।



पृष्ठभूमि: भारत को मिशन-मोड में निर्यात प्रोत्साहन की आवश्यकता क्यों है? रिजल्ट का साथी

भारत की \$5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा निर्यात-आधारित विकास पर टिकी है। हालाँकि, MSMEs—जो रोजगार और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं—को कुछ संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है:

- वहनीय (Affordable) व्यापार वित्त तक सीमित पहुँच।
- वैश्विक प्रमाणपत्रों के लिए उच्च अनुपालन लागत।
- रसद (Logistics) संबंधी कमियाँ, विशेष रूप से भीतरी जिलों में।
- सूचना की विषमता (Information asymmetry) और कमजोर बाजार बुद्धिमत्ता।
- विदेशों में अपर्याप्त भंडारण (Warehousing) और खरीदार कनेक्टिविटी।

संस्थागत वास्तुकला: EPM के दो स्तंभ

मिशन को दो एकीकृत उप-योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है:



1. निर्यात प्रोत्साहन – वित्तीय संबल (Financial Enablers): व्यापार वित्त और ऋण सहायता तक पहुँच में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
2. निर्यात दिशा – गैर-वित्तीय और बाजार पहुँच संबल (Non-Financial Enablers): अनुपालन, रसद, ब्रांडिंग, इंटेलिजेंस और विदेशी बाजार एकीकरण की समस्याओं का समाधान करता है।

'निर्यात प्रोत्साहन' के तहत मुख्य हस्तक्षेप

- **वैकल्पिक व्यापार उपकरण (निर्यात फैक्ट्रिंग):** कार्यशील पूंजी (Working Capital) को अनलॉक करने के लिए फैक्ट्रिंग को बढ़ावा देता है। इसमें ₹50 लाख प्रति IEC तक 2.75% ब्याज सहायता मिलती है।
- **ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट:** भारतीय निर्यात-आयात बैंक (EXIM Bank) के माध्यम से कार्यान्वित:
 - प्रत्यक्ष ई-कॉमर्स निर्यात के लिए 90% तक गारंटी कवरेज प्रदान करता है।
 - विदेशों में इन्वेंट्री-आधारित पूर्ति (Fulfilment) को प्रोत्साहित करता है।
- **उभरते निर्यात अवसर:** नए या उच्च-जोखिम वाले बाजारों में प्रवेश को प्रोत्साहित करने के लिए जोखिम-साझाकरण सहायता (10%–90%)।
- **ब्याज सहायता और संपार्श्विक-मुक्त ऋण:** पूर्व और बाद के शिपमेंट क्रेडिट के लिए 2.75% ब्याज सहायता। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 85% तक ऋण गारंटी कवरेज।

'निर्यात दिशा' के तहत मुख्य हस्तक्षेप

- **TRACE (व्यापार विनियम, प्रत्यायन और अनुपालन सक्षमता):** MSMEs को CE मार्किंग, FDA अनुमोदन, ISO मानकों जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है। (₹25 लाख सालाना तक 60-75% वित्तीय सहायता)।
- **LIFT (माल ढुलाई और परिवहन के लिए रसद हस्तक्षेप):** अंतर्देशीय माल ढुलाई लागत (₹20 लाख की सीमा) के लिए 30% तक सहायता प्रदान करता है।
- **INSIGHT (व्यापार बुद्धिमत्ता और सुविधा):** टूलकिट, एनालिटिक्स, प्रशिक्षण और क्लस्टर-स्तरीय सहायता के लिए धन प्रदान करता है।
- **FLOW (विदेशी भंडारण और पूर्ति):** विदेशी भंडारण, पूर्ति केंद्रों और ई-कॉमर्स केंद्रों का समर्थन करता है। (परियोजना लागत के 30% तक सहायता)।
- **मार्केट एक्सेस सपोर्ट (MAS):** व्यापार मेलों, खरीदार-विक्रेता बैठकों और प्रतिनिधिमंडलों के लिए वित्तीय सहायता।

निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को अंत-से-अंत (End-to-End) सहायता

चरण	सहायता
बाजार अन्वेषण	व्यापार बुद्धिमत्ता और एनालिटिक्स
शिपमेंट-पूर्व	क्रेडिट और ब्याज सहायता
अनुपालन	प्रमाणन सहायता
रसद (Logistics)	माल ढुलाई सहायता
विदेशी उपस्थिति	भंडारण और पूर्ति

भारत की निर्यात रणनीति के लिए महत्व

- **MSME प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती:** क्रेडिट और अनुपालन अंतराल को संबोधित करके वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।
- **निर्यात विविधीकरण:** जोखिम-साझाकरण उपकरण नए बाजारों में प्रवेश को प्रोत्साहित करते हैं।
- **डिजिटल एकीकरण:** सीमा पार ई-कॉमर्स के लिए समर्थन डिजिटल व्यापार विस्तार के अनुरूप है।



चुनौतियां और आगे की राह

चुनौतियां: बड़े पैमाने पर सब्सिडी की वित्तीय स्थिरता, मौजूदा योजनाओं के साथ दोहराव का जोखिम और जिलों में कार्यान्वयन क्षमता की कमी।

आगे की राह:

- पारदर्शिता के लिए रियल-टाइम डैशबोर्ड विकसित करना।
- EPM को मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) और PLI योजनाओं के साथ एकीकृत करना।
- "निर्यात हब के रूप में जिले" के तहत जिला-स्तरीय निर्यात सेल को मजबूत करना।

निष्कर्ष

निर्यात प्रोत्साहन मिशन भारत के निर्यात शासन में एक संरचनात्मक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है—खंडित सहायता योजनाओं से एक एकीकृत और मिशन-संचालित वास्तुकला की ओर। यदि प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो EPM MSMEs को स्थानीय उत्पादकों से वैश्विक खिलाड़ियों में बदलने की भारत की रणनीति का आधार स्तंभ बन सकता है।



UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. निर्यात प्रोत्साहन मिशन (EPM) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे दो उप-योजनाओं — निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा — के माध्यम से लागू किया जाता है।
2. TRACE निर्यात के लिए आवश्यक अंतरराष्ट्रीय प्रमाणों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
3. LIFT एमएसएमई निर्यातकों को आंतरिक परिवहन लागत की 100% प्रतिपूर्ति प्रदान करता है।
4. EPM के अंतर्गत निर्यात फैक्टोरिंग सहायता में ब्याज सब्सिडी (Interest Subvention) शामिल है।

उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

- A) केवल 1 और 2
- B) केवल 1, 2 और 4
- C) केवल 2 और 3
- D) केवल 1, 3 और 4

उत्तर: B) केवल 1, 2 और 4

प्रश्न 2. निर्यात प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित हस्तक्षेपों पर विचार कीजिए:

1. ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए ऋण सहायता
2. विदेशी भंडारण एवं पूर्ति (Fulfilment) सहायता
3. उभरते निर्यात बाजारों में प्रवेश हेतु जोखिम-साझेदारी सहायता
4. कार्बन सीमा कर समायोजन तंत्र

उपरोक्त में से कौन से EPM के घटक हैं?

- AS-PCS Institute
- R
- Result Mitra
- रिजल्ट का साथी
- A) केवल 1 और 2
 - B) केवल 1, 2 और 3
 - C) केवल 2 और 4
 - D) केवल 1, 3 और 4

उत्तर: B) केवल 1, 2 और 3

UPSC मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न. निर्यात प्रोत्साहन मिशन खंडित (Fragmented) निर्यात सहायता योजनाओं से एक एकीकृत पारितंत्र (Integrated Ecosystem) दृष्टिकोण की ओर परिवर्तन को दर्शाता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए तथा भारत में एमएसएमई-आधारित निर्यात वृद्धि को सुदृढ़ करने में इसकी संभावनाओं का विश्लेषण कीजिए। (15 अंक)



@resultmitra



www.resultmitra.com



9235313184, 9235440806

OPTIONAL SUBJECT
वैकल्पिक विषय
PSIR
Fee - मात्र 6999 ₹
केवल 01 से 06 जुलाई
Dr. Faiyaz Sir

(वैकल्पिक विषय) Optional Subject
GEOGRAPHY
OPTIONAL
Fee - मात्र 6499 ₹
केवल 21 से 26 जून